राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5385/2024

मुकेश कुमार खेदड़ पुत्र स्व. भोलूराम खेदड़, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम ढालियावास, पुलिस थाना श्री माधोपुर, जिला। सीकर (राज.) (वर्तमान में चूरू जिला जेल में) ------याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. दिनेश कुमार पुत्र शिशुपाल, निवासी ब्लॉड छोटी, फ़तेहपुर सदर, जिला। सीकर (राजस्थान) ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री राघवेन्द्र मुंडेल

प्रतिवादी के लिए: सुश्री सोनू मनावत, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>17/09/2024</u>

1. चूरू के सुजानगढ़ के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 20/2023 में पारित दिनांक 30.04.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जो 14.04.2023 को पुलिस स्टेशन सालासर में दर्ज एफआईआर संख्या 43/2023 से उत्पन्न हुआ था, जिसमें आईपीसी की धारा 302, 392, 34 के तहत कथित अपराध किए गए थे।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं: 2.1 याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर संख्या 43/2023 14 अप्रैल, 2023 को चूरू के सालासर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता शिशुपाल और एक अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार हरियाणा के नरवाना से सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम में गेहूं ले जा रहे थे। 13 अप्रैल, 2023 को शिकायतकर्ता को पुलिस से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि शिशुपाल को एक वाहन के नीचे कुचल दिया गया है और उसकी मौत हो गई है। जांच करने पर उसने आरोप लगाया कि मुकेश और रिछपाल नामक एक व्यक्ति ने शिशुपाल की हत्या कर दी है और उसके शव को वाहन के नीचे छिपा दिया है। इसके बाद, 14 जून, 2023 को याचिकाकर्ता और एक सह-आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 392 और 34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

2.1 याचिकाकर्ता ने 4 नवंबर, 2023 को जमानत याचिका दायर की। उसने जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो, कॉल विवरण और मामले से संबंधित स्थान रिपोर्ट शामिल हैं, तक पहुंच के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया। ट्रायल कोर्ट ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता से आवेदन का समर्थन करने वाले कानूनी प्रावधानों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा।

2.2. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 4 दिसंबर, 2023 को सीआरपीसी की धारा 207 और 208 के तहत एक आवेदन दायर किया। हालांकि, यह आवेदन विवादित आदेश के तहत था। इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और सरकारी वकील के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि सीआरपीसी की धारा 207 के अनुसार, अभियुक्त को उन सभी दस्तावेजों और सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य है, जिन पर अभियोजन आधारित है। याचिकाकर्ता को कोई भी अनुरोधित साक्ष्य नहीं मिला है, जो उसके बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता विवादित आदेश को अलग करके इसे प्रदान किए जाने का हकदार है, वह इसके लिए प्रचार करेगा।

5. शुरू में ही ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट इस तथ्य से काफी प्रभावित हुआ है कि जब याचिकाकर्ता को आरोप पत्र की प्रति दी गई थी, तो उसके द्वारा मांगी गई प्रासंगिक जानकारी भी उपलब्ध कराई गई थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का दावा है कि यद्यपि आरोप पत्र अन्य सामग्री के साथ दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा आवेदन के अनुसार मांगे गए साक्ष्य शामिल नहीं किए गए थे।

6. ट्रायल कोर्ट द्वारा यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अनुरोधित साक्ष्य वास्तव में दिए गए थे या नहीं। इसके बजाय, न्यायालय ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षरों के आधार पर यह मान लिया कि याचिकाकर्ता के वकील को सामग्री उपलब्ध करा दी गई थी, जिसमें न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र में संलग्न दस्तावेज भी शामिल थे।

7. उपरोक्त के अलावा, भारत का संविधान प्रत्येक अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक पहलू है। याचिकाकर्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य तक पहुंच से वंचित करना उसके लिए पर्याप्त बचाव तैयार करने के अधिकार का उल्लंघन है, जो उसके मुकदमे को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कई अनुरोधों के बावजूद, आवश्यक दस्तावेज़ और सामग्री प्रदान करने से ट्रायल कोर्ट का इनकार, कार्यवाही की निष्पक्षता को कमज़ोर करता है और इस मुकदमे को

न्याय की विफलता में बदलने का जोखिम उठाता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल में निष्पक्षता और सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की उपलब्धता आवश्यक है, खासकर हत्या जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में।

8. धारा 207 सीआरपीसी अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दिए गए सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ और साक्ष्य की आपूर्ति को अनिवार्य बनाती है। यह एक वैधानिक कर्तव्य है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अभियुक्तों को उनके खिलाफ आरोपों और सबूतों को समझने में सक्षम बनाता है। अनुरोधित दस्तावेज़ों (जैसे, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो, कॉल विवरण) तक पहुँच प्रदान करने से ट्रायल कोर्ट का इनकार इन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सीधा उल्लंघन है। भले ही आरोप पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोधित विशिष्ट सामग्री शामिल नहीं की गई थी। इसलिए, अदालत का यह अनुमान कि सभी आवश्यक साक्ष्य प्रदान किए गए थे, अनुचित है। ऐसा न करना निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त को ऐसे साक्ष्य तक पहुंच से वंचित न किया जाए जो उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद कर सकते हैं या अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

9. आपराधिक न्यायशास्त्र में, अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। साक्ष्य से इनकार करने से याचिकाकर्ता की खुद का बचाव करने की क्षमता सीधे तौर पर बाधित होती है, खासकर ऐसे मामले में जहां आरोप इतने गंभीर प्रकृति के हों। अनुरोधित साक्ष्य तक पूरी पहुँच के बिना, अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती देने और दोषमुक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर गंभीर रूप से समझौता किया जाता है। अनुरोधित साक्ष्य को फिर से प्रस्तुत करना, भले ही यह मान लिया जाए कि वही पहले भी प्रदान किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले

को पूर्वाग्रह या नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि "दोषी साबित होने तक निर्दोष" के सिद्धांत का सम्मान किया जाए।

10. याचिकाकर्ता द्वारा माँगी गई सामग्री की प्रासंगिकता की बात करें, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और कॉल विवरण, तो वे सबूत के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं। ये या तो अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि कर सकते हैं या बचाव का समर्थन करने वाला प्रति-कथन प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कॉल विवरण रिकॉर्ड और स्थान रिपोर्ट यह दिखा सकती है कि याचिकाकर्ता या अन्य आरोपी अपराध स्थल पर मौजूद थे या नहीं। ऐसे साक्ष्य तक पहुँच से इनकार करके, न्यायालय प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाने का अवसर देने से इनकार कर रहा है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकती है। प्रभावी जिरह और बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार सीआरपीसी में निहित है और गलत दोषसिद्धि को रोकने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अनुरोधित साक्ष्य प्रदान करने से अभियोजन पक्ष के मामले को अनुचित नुकसान या पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके विपरीत, यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास जगाएगा। अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपना मामला तैयार कर लिया है, और इसलिए, साक्ष्य को फिर से साझा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। यह केवल याचिकाकर्ता को उचित बचाव के लिए अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

11. यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता पर धारा 302 आईपीसी (हत्या) के तहत आरोप लगाया गया है, संभावित दंड गंभीर हैं, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी शामिल है। याचिकाकर्ता को अपना बचाव पूरी तरह से करने का हर अवसर दिया जाना चाहिए, खासकर ऐसे मामले में जहां साक्ष्य प्रस्तुत करने में थोड़ी सी भी लापरवाही अपरिवर्तनीय परिणामों को जन्म दे सकती है। ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की संभावित

विफलता को रोकने के लिए बचाव पक्ष को सभी प्रासंगिक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं।

12. मांगी गई सूचना न दिए जाने के गंभीर परिणामों को देखते हुए, मेरा मानना है कि इस बात पर अनावश्यक विवाद में पड़े बिना कि इसे आरोप पत्र में शामिल किया गया था या नहीं, यदि याचिकाकर्ता को मांगे गए साक्ष्य फिर से दिए जाते हैं तो अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा।

13. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। 30.04.2024 का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। 04.12.2023 के आवेदन में मांगी गई सूचना, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ट्रायल को आगे बढ़ाने से पहले याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।